

## बिहार गजट

## असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 फाल्गुन 1945 (श0) पटना, बुधवार, 20 मार्च 2024

(सं0 पटना 306)

सं० 27/आरोप-01-43/2020 सा0प्र0-2173 सामान्य प्रशासन विभाग

## संकल्प 5 फरवरी 2024

श्रीमती रेणु कुमारी, बिठप्र०से०, कोटि क्र0—1242/11 तत्का० जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3632 दिनांक 23.09.2020 द्वारा आरोप पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। शेल्टर होम में हो रही अनियमिताओं के संबंध में सी.बी.आई. से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय त्रि—सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उच्च स्तरीय त्रि—सदस्यीय समिति द्वारा श्रीमती रेणु कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गयी। आरोप पत्र में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कैमूर के रूप में अपनी पदस्थापन अविध दिनांक 05.06.2014 से 06.04.2015 के बीच इनके द्वारा अल्पावास गृह, कैमूर का एक बार भी समीक्षा एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिससे अल्पावास गृह में कई प्रकार की अनियमितताएं प्रकाश में नहीं आ सकीं।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति साक्ष्य अभिलेखों सहित विभागीय पत्रांक—9343 दिनांक—09.06.2022 द्वारा भेजते हुए श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के पत्र दिनांक—09.02.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्रीमती रेणु कुमारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि महिला विकास निगम, बिहार के पत्रांक 1105 दिनांक 10.10.2013 की कंडिका—6(x) में प्रावधानित है कि अल्पावास गृह के लिए एक समीक्षा समिति होगी, जो इसमें प्रवास कर रहे संवासिनों के मामले में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में समीक्षा करेंगी। समीक्षा के दौरान गत माह में संवासिनों के रख—रखाव, खान—पान, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास आदि की समीक्षा की जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष जिला प्रोग्राम पदाधिकारी होते हैं। श्रीमती रेणु कुमारी द्वारा अपने पदस्थापन काल में नियमित रूप से अल्पावास गृह का समीक्षा नहीं किया गया, जिसके कारण अल्पावास गृह में व्याप्त त्रुटियों का निराकरण संभव नहीं हो पाया। तदुपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6170 दिनांक 31.03.2023 द्वारा श्रीमती कुमारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम 14 के संगत प्रावधानों के तहत निन्दन

(आरोप वर्ष—2014—15) एवं दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किये जाने की शास्ति अधिरोपित की गयी है।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा एक पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 09.05.2023 समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12858 दिनांक 07.07.2023 द्वारा अधिरोपित दंड को यथावत रखा गया है।

पुनः श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक 31.01.2024 को दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन दिया गया, जिसमें उनका मूल रूप से कहना है कि दिनांक 05.06.2014 से 06.04.2015 तक की अविध में उन्हें डी०पी०ओ० / आई०सी०डी०एस० इंचार्ज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उनके द्वारा प्रभार की अविध में नियमानुकूल कार्यों का निस्पादन किया गया है। उनका कहना है कि इस हेतु उपलब्ध मार्गदर्शिका के अन्तर्गत डी०पी०ओ० / आई०सी०डी०एस० को अल्पावास गृह के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का निदेश नहीं किया गया था। अतः निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार आरोप के इस बिन्दू को निराधार बताया गया है।

श्रीमती रेणु कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, त्रि—सदस्यी समिति की अनुशंसा, अधिरोपित दंड एवं उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक 31.01.2024) की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्रीमती कुमारी लगभग 10 महीने तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित रहीं। श्रीमती कुमारी के विरूद्ध कोई वित्तीय अनियमितता या गंभीर अनुशासनहीनता का आरोप नहीं है। उनके विरूद्ध दायित्वों के तहत समीक्षा / निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में चुक से संबंधित है। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6170 दिनांक 31.03.2023 द्वारा अधिरोपित शास्ति को संशोधित करते हुए श्रीमती रेणु कुमारी, बि०प्र०से० को निन्दन (आरोप वर्ष 2014—15) का दंड विनिष्टिचत किया गया है।

अतएव श्रीमती रेणु कुमारी, बि0प्र0से0, काटि क्र0—1242 / 11 तत्का0 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6170 दिनांक 31.03.2023 द्वारा अधिरोपित शास्ति को संशोधित करते हुए निन्दन (आरोप वर्ष 2014—15) का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

> बिहार—राज्यपाल के आदेश से, रबिन्द्रनाथ चौधरी, उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । बिहार गजट (असाधारण) 306-571+10-डी0टी0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in